भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 4 * दि. 16 से 31 जुलाई 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

आदिवासी जमीन सौदे पर बड़ा खुलासा 'सेवन इलेवन' से वापस लेंगे जमीन

विस में राजस्व मंत्री बावनकुले का ऐलान

सन संवाददाता

मीरा-भायंदर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे वर्सोवा गांव में आदिवासी जमीन की कथित अवैध खरीद का मामला गुरुवार को विधानसभा में गूंजा. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सदन को बताया कि वर्ष 2017 में सेवन इलेवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदी गई आदिवासी जमीन की जांच में अनियमितता सामने आई है, इसलिए यह जमीन वापस आदिवासी परिवारों को लौटाई जाएगी. विधानसभा में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार और नाना पटोले ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी 'सेवन इलेवन प्राइवेट लिमिटेड' ने आदिवासियों की जमीन

नियमों के विपरीत खरीदी थी.

भाजपा MLA मेहता पर लगाया था आरोप

इस पर जवाब देते हुए मंत्री बावनकुले ने कहा कि सरकार आदिवासी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है. बता दें कि चेना-वरसावे के करीबन 13 आदिवासी परिवारों ने जमीन हड़पने का आरोप भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर लगाया था और राजस्व मंत्री से शिकायत की थी, जिसकी जांच का आदेश उन्होंने दिया था. जिलाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट राजस्व मंत्री को सौंप दी थी. रिपोर्ट में जमीन की खरीद में अनियमितता जैसे अधूरा भुगतान, जोर-जबरदस्ती करने की टिप्पणी की गई थी. हालांकि विधायक मेहता ने तब दावा किया था कि राज्य सरकार से अनुमति के बाद आदिवासी परिवारों ने उनकी कंपनी को जमीन बेची थी. मामला 10-12 साल पुराना है. वहीं एक अन्य जमीन मामले में मंत्री बावनकुले ने बताया कि मीरा-भाईंदर क्षेत्र की बड़ी मात्रा में जमीन ब्रिटिश काल में पट्टे पर दी गई थी, जिसमें मीरा भाईंदर की 318 एकड़ भूमि पर मीरा सॉल्ट कंपनी ने मालिकाना दावा किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपये है. यह जमीन भी पट्टे पर दी गई थी. हालांकि हाई कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने हाल ही में इस भूमि को द्वितीय श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है. राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्यभर में मंदिरों की करीब 1.63 लाख हेक्टेयर भूमि पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है.

मीरा-भाईंदर में गुटखे का काला कारोबार

आखिर किसकी शह पर फल-फूल रहा है यह जहर ?

सन संवाददाता

मीरा-भाईंदर में काशीमीरा में मुंशी कंपाउंड में कृष्णा अथल भोलापन वाला, ए आर पैराडाइज़ होटल के बगल में पान की दुकान है , भयंदर पूर्व भाजी मार्केट में, इन सभी पान की दुकानों में गुटखा (Gutkha) खुलेआम बेचा जा रहा है भयंदर पूर्व भाजी मार्केट -काशीमीरा तक प्रतिबंधित गुटखे का कारोबार खुलेआम चल रहा है जबकि महाराष्ट्र सरकार अब राज्य में प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू की अवैध बिक्री, भंडारण और परिवहन करने वाले माफियाओं के खिलाफ मकोका (MCOCA – Maharashtra Control of Organised Crime Act) के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। भयंदर पूर्व भाजी मार्केट ,काशीमीरा मुंशी कंपाउंड में कृष्णा अथल , ए आर पैराडाइज़ होटल के बगल में पान की दुकानों, छोटे ठेलों और गुप्त ठिकानों पर गुटखा आसानी से मिल रहा है, मानो इस पर कोई प्रतिबंध ही न हो।

गुप्त सूत्रों के अनुसार से पता चला है की नवधर पुलिस और काशिमीरा पुलिस इन गुटखा कारोबारीयों से 3000-3500/ हर महिने हफ्ता लेते है। इन्हीं की संरक्षण में गुटखा (Gutkha) कारोबारी बिना डर- भय के गुटखा (Gutkha) बेच रहे है। महाराष्ट्र सरकार ने गुटखा और सुगंधित तंबाकू की बिक्री पर 2012 में प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद राज्य और शहर में खुलेआम इसकी बिक्री होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा गुटखा नेटवर्क आखिर किसकी नजरों से बचकर चल रहा है? गुटखा शहर में आ कहाँ से रहा है? कौन लोग इसकी सप्लाई कर रहे हैं? किन दुकानों और गोदामों से इसका वितरण हो रहा है? इन सवालों का जवाब न तो पुलिस के पास दिखाई देता है और न ही उस विभाग के पास जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर इस पर कार्रवाई करना है।

गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की होती है। लेकिन मीरा-भाईंदर क्षेत्र में यह विभाग जैसे गायब सा हो गया है। न तो छापेमारी की खबरें सामने आती हैं और न ही बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई दिखाई देती है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रशासन इस काले कारोबार से अनजान है, या फिर जानबूझकर आंखें मूंदे हुए है? लेकिन शहर में जिस तरह से प्रतिबंधित गुटखे का कारोबार फैल रहा है, उससे पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस चाहे तो कुछ ही दिनों में इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि गुटखा बेचने वाली दुकानों और सप्लाई करने वाले लोगों की जानकारी आम लोगों को भी है ।

गुटखा सिर्फ एक अवैध कारोबार नहीं, बल्कि समाज के लिए एक धीमा जहर है। युवाओं और मजदूर वर्ग में इसकी लत तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। बावजूद इसके, इसका बाजार लगातार फैलता जा रहा है।

मीरा-भाईंदर के नागरिक अब यह जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस और FDA विभाग इस काले कारोबार पर सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या गुटखा माफिया के नेटवर्क का पर्दाफाश होगा ? या फिर यह जहरीला कारोबार इसी तरह खुलेआम चलता रहेगा और जिम्मेदार विभाग सिर्फ मूकदर्शक बने रहेंगे।

MBMC में 12 करोड़ के ठेके पर बवाल

बिना ई-टेंडर बीजेपी से जुड़ी कंपनी को मंजूरी का आरोप

सन संवाददाता

मीरा भाईंदर महानगरपालिका में 12 करोड़ के ठेके को बिना ई-टेंडर मंजूरी देने पर विवाद गहराया। राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच स्वतंत्र जांच व कार्रवाई की मांग उठी।

मीरा- भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) की स्थायी समिति द्वारा 150 कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए बिना ई-टेंडर प्रक्रिया अपनाए नई एजेंसी को मंजूरी दिए जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों ने इस निर्णय को नियमों के विपरीत बताते हुए राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई और स्वतंत्र जांच की मांग उठी है, जबकि मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने शिकायत पर अतिरिक्त आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। स्थायी समिति ने 3 जुलाई 2026 को 150 कर्मियों की आपूर्ति के लिए 'ओम साई सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट' को बिना ई-टेंडर, अनुबंध देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि कंपनी कर्मचारियों को समय पर वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसी वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है।

विवाद इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि इससे पहले कार्यरत 'स्वामी समर्थ सिक्योरिटी एंड हॉस्पिटैलिटी प्रा. लि.' का अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुका था। मनपा के आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार, उस कंपनी को वेतन भुगतान, सुरक्षा उपकरण, वर्दी उपलब्ध न कराने और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन सहित 19 नोटिस जारी किए गए थे। सत्याकाम फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं एड. कृष्णा गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने जानबूझकर समय पर नई निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं की, ताकि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की अनुसूची ' ड 'अध्याय-5, नियम 2(2) के आपातकालीन प्रावधान का सहारा लेकर पसंदीदा ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा सके। एड. कृष्णा गुप्ता का कहना है कि मनपा आयुक्त द्वारा 7 अगस्त 2025 को सभी विभागों को समय रहते नई निविदा प्रक्रिया पूरी करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि 22 मई 2026 को आरोग्य विभाग की उपायुक्त कविता बोरकर ने करीब 12 करोड़ रुपये के नियमित ई-टेंडर का प्रस्ताव महासभा में रखा था, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद 3 जुलाई को बिना ई-टेंडर उसी कार्य के लिए आपातकालीन प्रावधान के तहत प्रस्ताव लाकर स्थायी समिति से मंजूरी दिला दी गई। ई-टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर नियमों की अनदेखी की गई और इससे राजनीतिक संरक्षण के आरोपों को बल मिला है। उनका कहना है कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच का विषय भी हो सकता है। इस पूरे मामले में एड. कृष्णा गुप्ता ने उपायुक्त कविता बोरकर के निलंबन, विभागीय जांच तथा किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने अतिरिक्त आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी है।

संपादकीय

सुनें तार्किक विरोध

भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती रही है कि यहां हर अलग राय व असहमति को सम्मान मिला है। निश्चय ही यह दृष्टि लोकतंत्र को मजबूत ही करती है। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो प्रतिरोध की आवाज को सुनने के लिये नीति-नियंताओं को बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। एक बार फिर इस भावना की परीक्षा तब हो रही है, जब हमारे देश में लाखों बच्चों का भविष्य तय करने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे हैं। परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाये रखने के लिये शिक्षाविद् और इनोवेटर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर देश में चिंता है। उनका वजन काफी कम हुआ है, रक्त शकर्रा कम हुई है और कमजोरी आने की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से हटकर उनकी खराब होती सेहत हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। निश्चय ही वांगचुक किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते और न ही वे यह आंदोलन किसी निजी लाभ के लिये कर रहे हैं। वे भले ही छात्रों के भविष्य के मुद्दे को लेकर अस्तित्व में आई- 'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थन में खड़े हुए हों, लेकिन उनकी चिंता के केंद्र में उन लाखों छात्रों का भविष्य है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के तौर-तरीकों को लेकर अविश्वास जता रहे हैं। उनके आंदोलन के मूल में उन लाखों अभिभावकों की फिक्र है, जिनका भरोसा बार-बार पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को लेकर डगमगा रहा है। कहना मुश्किल है कि लगाया जा रहा हर आरोप सही ही हो, लेकिन एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की कई महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में लोगों का विश्वास कम हुआ है। ऐसे में देश के नीति-नियंताओं को पारदर्शी सुधार लाकर और बेहतर जवाबदेही के माध्यम से दरके हुए विश्वास को जल्द बहाल करने की जरूरत है।

निर्विवाद रूप से ये लोकतंत्र का तकाजा भी है कि सत्ताधीशों को किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन नागरिकों की बात को भी सुनना चाहिए, जो नीतियों की विसंगतियों को लेकर सवाल उठा रहे हों। यह जानते हुए कि उनकी राजनीतिक दल विशेष से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। निस्संदेह, देश में कोई भी सरकार जनता के अभिभावक के रूप में होती है। वैसे भी किसी शांतिपूर्ण विरोध की लंबे समय तक अनदेखी से आंदोलनकारियों और आम लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है। निस्संदेह, यदि आंदोलनकारियों से बातचीत की पहल होती है तो इसको उसकी कमजोरी नहीं कहा जाएगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भूख हड़ताल के नैतिक और चिकित्सीय पहलू भी होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह आंदोलन कर रहे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हुए उसके जीवन की रक्षा करे। वहीं दूसरी ओर किसी भी चिकित्सीय हस्तक्षेप के दौरान कानून और चिकित्सा-संबंधी नैतिक नियमों का पालन किया जाना भी जरूरी है। इस बात में दो राय नहीं है कि मौजूदा गतिरोध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। सही मायने में बातचीत की शुरुआत करने के लिये सरकार को हर मांग को पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों को भी बातचीत को सार्थक बनाने के लिये प्रयासरत रहने की जरूरत है। ऐसे में समस्या के समाधान के लिये एक भरोसेमंद समिति और चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिये एक तय समय-सीमा वाला रोडमैप, भरोसे की कमी को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। सही मायने में इस आंदोलन के मानवीय पक्ष पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यानी सरकार समझने की कोशिश करे कि इस आंदोलन के जन्म लेने के पीछे क्या भावनाएं काम कर रही थीं। साथ ही सरकार को शांतिपूर्ण विरोध के मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से बातचीत के लिये किया गया कोई ईमानदार प्रयास गतिरोध को दूर करने में सहायक साबित हो सकता है। साथ ही इस बात की संवेदनशीलता का ध्यान रखना भी जरूरी है कि शासन की शिथिलता व उदासीनता की कीमत सोनम वांगचुक की सेहत को न चुकानी पड़े।

दुनिया के लिए सबक यूरोप की असामान्य गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार यूरोप महाद्वीप के कई हिस्सों में हीट डोम बना हुआ है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज की गर्मी हर दिन इसमें वृद्धि करती है। नतीजतन, बारिश और ठंडी हवाएं भी राहत नहीं दे पातीं।

ग्लोबल वार्मिंग ने दुनियाभर में कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो गई है। अब तापमान वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रहा है। इसके चलते लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।

यूरोप की भीषण गर्मी इस बात की चेतावनी है। यूरोप की इस गर्मी को 'हीट डोम' कहें, 'हीटवेव' कहें या फिर उसे 'ओमेगा हीटवेव' की संज्ञा दी जाए, हकीकत यह है कि यूरोप भीषण गर्मी के साये में झुलस रहा है। यूरोप के कई देश 1970 के दशक की तुलना में दो महीने अधिक 'हीट स्ट्रेस' का भीषण असर झेल रहे हैं। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार यूरोप महाद्वीप के कई हिस्सों में हीट डोम बना हुआ है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज की गर्मी हर दिन इसमें वृद्धि करती है। नतीजतन, बारिश और ठंडी हवाएं भी राहत नहीं दे पातीं। हीट डोम बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। इससे लोग लंबे समय तक गर्मी झेलने को मजबूर होते हैं। इस समय फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली की सरकारों ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। पूरे स्पेन में गर्मी का अलर्ट है। बेल्जियम और नीदरलैंड में भीषण गर्मी के चलते अभी तक 3700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्थानीय अधिकारियों की मानें तो आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रांस के अधिकांश हिस्सों में हाई अलर्ट है। वहां के 54 विभागों में रेड अलर्ट है। यहां 1947 के बाद इस बार भीषण गर्मी देखी गई है।

हालात इतने खराब हैं कि गर्मी से राहत पाने की कोशिश में वहां जलाशयों व नदियों में गए तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। एफिल टावर के पास ट्रोकाडेरो फाउंटेन में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग कूदते देखे गए हैं। यही नहीं, वहां घरों में रहने वाले 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मौतों की

तादाद सबसे ज्यादा, यानी 91 फीसदी है। बेल्जियम और नीदरलैंड में भी सबसे ज्यादा 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मौतें हुई हैं। यह हालात की भयावहता का जीता-जागता सबूत है। इन हालातों ने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को बढ़ा दिया है। परिवहन सुविधाओं पर भी काफी दबाव पड़ा है। लोग मानने लगे हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीरता से लेने का समय आ गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार यूरोप में गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। वैज्ञानिक इसे 'ओमेगा ब्लॉक' नामक दुर्लभ मौसमी पैटर्न की संज्ञा दे रहे हैं। उनके अनुसार ओमेगा ब्लॉक के चलते यूरोप के कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। स्कूल बंद करने पड़े हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है और पोल्ट्री फार्मों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस असामान्य गर्मी के पीछे 'ओमेगा ब्लॉक' नामक मौसमी पैटर्न है, जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र ग्रीक अक्षर 'ओमेगा' के आकार का बन जाता है। यह गर्म हवा को लंबे समय तक एक ही इलाके में रोककर रखता है, जिससे अमूमन तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो सकता है।

फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी शहर पिसोस में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। उत्तर-पश्चिमी शहर ब्रिटनी में बिजली आपूर्ति ठप रही है। वहीं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भी उत्पादन में सात फीसदी की कटौती करने को बाध्य होना पड़ा है। इसका कारण शीतलन के लिए वहां पर्याप्त पानी का अभाव था। इससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है।

वहीं, इटली में सोलह शहरों में उच्च स्तर का हाई अलर्ट जारी करना पड़ा है। ब्रिटेन में बढ़ते तापमान के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा। फ्रांस में कारों में अत्यधिक तापमान के कारण कई छोटे बच्चे मौत के मुंह में चले गए। यहां के ब्रिटनी और पेज दे ला लोआर इलाके के अनेक पोल्ट्री फार्मों में अत्यधिक गर्मी से लाखों पक्षियों की मौत हो गई।

दरअसल, अध्ययनों ने एक साल पहले ही चेता दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तीन गुना अधिक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। नेचर रिव्यू अर्थ एंड एनवायरमेंट में प्रकाशित किंग्स कॉलेज के अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, स्वस्थ और युवा वयस्कों को बढ़ती गर्मी के चलते होने वाली कठिनाई की सीमा तीन गुना होने की संभावना व्यक्त की गई थी। अध्ययनकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी जैसे हालात होंगे, वहां वृद्ध लोगों को गर्मी से 35 फीसदी अधिक खतरा होगा। अध्ययनकर्ता प्रोफेसर टॉम मैथ्यूज के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान में वृद्धि निर्धारित मानक के अनुपात में दो डिग्री तक पहुंच जाती है तो इसके घातक परिणाम होंगे। इससे वृद्ध लोगों को झुलसाने वाली गर्मी की सीमाएं बढ़ेंगी। वहीं, इससे युवा आने वाले समय में अधिक जूझते नजर आएंगे।

शोधकर्ताओं का दावा है कि असहनीय गर्मी में शरीर का मुख्य तापमान छह घंटे के भीतर 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह

ज़हरीली विरासत

शासन-प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद आज भी पंजाब की नदियों को जहरीला बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिसकी पुष्टि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्वीकृति है कि आज भी आठ सौ से अधिक प्रदूषण के स्रोत राज्य की नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। निश्चय ही यह तथ्य उन विभागों व संस्थाओं के कामकाज पर सवालिया निशान है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन से जुड़े हैं। साथ ही लंबे समय से अदालत के हस्तक्षेप व विभिन्न सर्वेक्षणों में सामने आए तथ्यों की पुष्टि होती है कि राज्य में जागरूकता की कमी नहीं है, बल्कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई न होने से उपजा संकट है। वर्षों से सरकारें एक्शन प्लान बनाने के दावे करती रही हैं। कभी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात होती है तो कभी कमेटियां बनाने के दावे होते हैं। आखिर क्यों आज भी बिना साफ किया हुआ सीवेज और औद्योगिक कचरा सतलुज,ब्यास और इनकी सहायक नदियों में बदस्तूर बहाया जा रहा है। जाहिर है, मौजूदा संसाधनों का या तो पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है या उनका रखरखाव ठीक नहीं है। फलतः जन-स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा संकट पैदा होता है। जो धीरे-धीरे आपदा का रूप ले लेता है। आज फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों के जरिये भारी धातुएं और जहरीले तत्व भूजल को प्रदूषित करने के बाद, हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो रहे हैं। जो राज्य के बहुचर्चित ' कैंसर बेल्ट' के रूप में हमारे सामने मौजूद है।

निस्संदेह, पंजाब में यदि हरित क्रांति का परचम लहराया तो उसके मूल में पंजाब की नदियों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आज वे तंत्र की काहिली, अनियोजित शहरीकरण, नियम-कानूनों का क्रियान्वयन न होने और दोषियों को सजा न मिलने का दंड चुका रही हैं। एनजीटी गाहे-बगाहे नगर निकायों की शिथिलता दर्शाकर सच्चाई से आम लोगों को अवगत कराता रहा है। निस्संदेह, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि इसकी जिम्मेदारी तय न की जाए और सख्त जुर्माना लगाना पर्यावरण संरक्षण नीति का हिस्सा नहीं बनता है। राज्य ने साबित किया है कि मरणासन्न नदियों को फिर से जीवित किया जा सकता है। काली बेईं को पुनर्जीवित करने में जागरूक लोगों की बड़ी भूमिका रही है। जो दर्शाता है कि पक्के इरादे के साथ किए गये प्रयास से बेहद बुरे हालात में पहुंच चुके जल स्रोत को भी जीवंत बनाया जा सकता है। लेकिन इक्का-दुक्का सफलताएं ही व्यापक रणनीति की जगह नहीं ले सकतीं। जरूरी है कि नियम-कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए, सार्वजनिक रिपोर्टिंग को पारदर्शी बनाएं तथा सीवेज एवं कचरा-शोधन प्रणालियों में निरंतर निवेश बढ़ाया जाए। सर्वविदित है कि पंजाब का नाम यहां की नदियों से पड़ा है। ऐसे में इन नदियों को खुले नाले बनते रहने देने से न केवल हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र व लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि राज्य की खुशहाली व पहचान के लिये भी एक खतरा है। अब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने का वक्त है।

वरिष्ठ पत्रकार कुमार महादेव व्यास चुने गए राजस्थान प्रेस क्लब अध्यक्ष

सन संवाददाता

मुंबई। महानगर के राजस्थानी प्रवासी पत्रकारों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था राजस्थान प्रेस क्लब की साधारण आम सभा होटल आदर्श पैलेस में सम्पन्न हुई। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने पर राजस्थान सूचना केंद्र प्रभारी / सहायक निदेशक ऋतु सोढ़ी एवं संस्थापक व चुनाव अधिकारी जगदीश पुरोहित के निर्देशन में संपन्न हुए चुनावों में वरिष्ठ पत्रकार कुमार महादेव व्यास अध्यक्ष चुने गए। व्यास रावल कार्यकारी अध्यक्ष, ललित शक्ति सचिव, रमेश काबरा कोषाध्यक्ष, हरीश राजावत संयुक्त सचिव, राहुल पारीक, जितेंद्र सिंह राठौड़, सुरेश भंसाली, ज्योति मुनौत, मनीष पालीवाल , डॉ प्रकाश सोनी, श्रीमति विद्या उत्तम शाह को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया।

वार्षिक साधारण सभा में अध्यक्ष कन्हैयालाल खंडेलवाल ने अपने स्वागत उद्बोधन में राजस्थान प्रेस क्लब की स्थापना की अवधारणा और उसके उद्देश्यों को रेखांकित किया। सचिव व्यास कुमार रावल ने तीन वर्षों के कार्यकाल की गतिविधियों का ब्यौरा दिया। कोषाध्यक्ष दिनेश्वर माली ने वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जिसका सभी ने अनुमोदन किया। पूर्व अध्यक्ष नीरज दवे ने कहा कि राजस्थान के प्रवासी पत्रकारों का इस महानगर में परस्पर सौहार्द और सकारात्मकता सामाजिक समरसता का शुभ संकेत है। वरिष्ठ मीडिया विशेषज्ञ निरंजन परिहार ने अपने संबोधन में पत्रकार संगठन की रीति नीति और क्रिया कलापों पर चर्चा की। राजस्थान सूचना केंद्र की सह आयुक्त रितु सोढ़ी ने पत्रकारों से राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं को प्रवासी राजस्थानियों तक पहुंचाने में उनके योगदान की अपील की। जगदीश पुरोहित ने नई कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा की। नव निर्वाचित अध्यक्ष कुमार महादेव व्यास ने अपने उद्बोधन में विश्वास व्यक्त किया कि सभी सा थि यों के सहयोग से प्रेस क्लब निरन्तर आगे बढ़ता रहेगा। सभा में राजस्थानी प्रवासी समाज के दिवंगत नेता राज के पुरोहित के दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई तथा प्रवासी समाज के उनके योगदान को सराहा गया। आम सभा का प्रारंभ गायत्री मंत्र के उच्चारण से किया गया।

अचार्य शैलेश पांडे ने अपने जन्मदिन पर भरत भूषण तिवारी को दी श्रद्धांजलि

सन संवाददाता

मीरा-भाईंदर । बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पिछले दिनों पुलिस एनकाउंटर में जिस तरह से आत्म समर्पण के बाद भी भरत भूषण तिवारी की पुलिस द्वारा निर्मम रूप गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, उससे व्यथित होकर संकल्प राष्ट्र सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास अयोध्या धाम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य शैलेश पांडेय ने मंगलवार को अपना जन्मदिन न मनाकर भायंदर पूर्व स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय भारत माता मंदिर सेवाश्रम में शहीद भरत भूषण तिवारी की श्रद्धांजलि और शोक सभा का आयोजन किया। उपस्थित लोगों ने भरत भूषण तिवारी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा मौन व्रत रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में आचार्य शैलेश पांडेय, मनपा शिक्षण समिति की सभापति स्नेहा शैलेश पांडे, परिवहन समिति के सभापति एड. राजकुमार मिश्रा, भाजपा जिला महामंत्री बृजेश तिवारी, पतंजलि योग समिति ठाणे जिला प्रमुख योग गुरु संतोष खटावकर, जिला सचिव मुकेश जांगिड़, जिला सचिव फूलकुमार झा, समाजसेवक एल आर पांडे, समाजसेवी मैना पांडेय, जितेंद्र प्रताप सिंह मंडल उपाध्यक्ष, विश्वनाथ तिवारी जिला सचिव, बी एस पाठक, संदीप दुबे, संजय दुबे, देवेंद्र सिंह, संजय गुप्ता, संदीप शर्मा, नितीन ओझा, विशाल रजक आदि का समावेश रहा।

आमदार नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष दिलीप जैन के मार्गदर्शन में, डॉ. सुरेश येवाले, परिवहन सभापती, एड राजकुमार मिश्रा और कार्यालय प्रमुख अन्ना असीनकर की मौजूदगी में, एडवोकेट योगेश जगदाले को भारतीय जनता पार्टी के विधी सेल का उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।

मीरा रोड के पेनकर पाड़ा में बारिश बनी विवाद की वजह

कोयता निकालने का वीडियो वायरल, समझौते के बाद नहीं दर्ज हुआ मामला

सन संवाददाता

मीरा रोड । पेनकर पाड़ा में बारिश का पानी घर में घुसने को लेकर पारिवारिक विवाद में कोयता निकालने का वीडियो वायरल हुआ। शिकायत न मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।

पेनकर पाड़ा इलाके में भारी बारिश के दौरान घर में पानी घुसने को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद कोयता निकलने तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग उठने लगी। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला दो परिवारों के बीच का घरेलू विवाद है और किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

विवाद का वीडियो हुआ वायरल

लगातार हो रही बारिश से बचाव के लिए एक परिवार अपने घर की छत और दीवारों पर प्लास्टिक लगा रहा था। इसी दौरान प्लास्टिक से बहता बारिश का पानी पड़ोसी के घर की ओर जाने लगा, जिससे दोनों परिवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर एक व्यक्ति ने प्लास्टिक काटने के उद्देश्य से कोयता हाथ में उठा लिया। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो वायरल होने के बाद इसे हमला और हिंसा की घटना बताकर प्रसारित किया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि मामला दो परिवारों के बीच का घरेलू विवाद था। पुलिस के अनुसार, कोयता प्लास्टिक काटने के लिए उठाया गया था और किसी पर हमला नहीं किया गया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अपुष्ट वीडियो और भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें।

शिकायत नहीं, समझौते के बाद मामला हुआ शांत

पुलिस जांच में सामने आया कि विवाद करने वाले दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ की और आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझा लिया। किसी भी पक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। शिकायत नहीं मिलने के कारण पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर या अन्य कानूनी कार्रवाई दर्ज नहीं की।

सड़क सुरक्षा पर सख्त हुई ट्रैफिक पुलिस

मीरा-भाईंदर में बढ़ते हादसों पर MBMC, MMRDA और NHAI से मांगा जवाब

मीरा भाईंदर शहर में सड़क निर्माण और अधूरी मरम्मत के बीच बढ़ते हादसों पर यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष महज 4 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दोगुनी हो गई है।

लगातार चेतावनी के बावजूद सड़क मरम्मत और सुरक्षा उपायों में सुधार नहीं होने पर मीरा-भाईंदर यातायात पुलिस ने मीरा भाईंदर मनपा (एमबीएमसी), एमएमआरडीए (एमएमआरडीए) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि सड़क हादसों में लापरवाही के लिए उन्हें आरोपी क्यों न बनाया जाए। शहर में एमएमआरडीए द्वारा मेट्रो निर्माण, एनएचएआई द्वारा मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंक्रीटीकरण और अन्य कार्य तथा नगर निगम की पाइपलाइन, केबल व विकास परियोजनाओं के कारण कई स्थानों पर खुदाई चल रही है। आरोप है कि कार्य पूरा होने के बाद समय पर सड़क मरम्मत, बैरिकेड हटाने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता गया। यातायात पुलिस के अनुसार, पिछले 4 महीनों में मीरा भाईंदर शहर में 21 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 7 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल और 4 अन्य को मामूली चोटें आईं। जबकि पूरे वर्ष 2025 में 14 दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस का कहना है कि संबंधित एजेंसियों को कई बार सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसी कारण अब एमएमआरडीए, एनएचएआई और नगर निगम को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पुलिस ने जिन प्रमुख लापरवाहियों की ओर इशारा किया है, उनमें काशीमीरा-दहिसर टोल प्लाजा मार्ग पर मेट्रो निर्माण के दौरान यातायात प्रबंधन की अनदेखी, दिन के व्यस्त समय में निर्माण कार्य कर यातायात प्रभावित करना, कार्य पूरा होने के बाद भी बैरिकेड समय पर नहीं हटाना, सड़कों के गड्ढों की समय पर मरम्मत नहीं करना, सड़क किनारे नालियों के टूटे ढक्कनों को खुला छोड़ना, रात के समय बैरिके पर पर्याप्त रिफ्लेक्टर, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं करना आदि मुद्दों का समावेश है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि सड़क मरम्मत और सुरक्षा उपायों में जल्द सुधार नहीं किया गया तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

बिल्डर की कथित लापरवाही के कारण 4 लोग घायल

निर्माणाधीन टावर की 24 वीं मंजिल से चॉल पर गिरा सीमेंट ब्लॉक!

सन संवाददाता

मीरा रोड । मीरा-भायंदर शहर के अधिकतर निर्माण स्थल पर बिल्डरों द्वारा खुलेआम सुरक्षा नियमों के प्रति बरती जा रही लापरवाही और मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन की अनदेखी ने सोमवार को चार लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया है। घटना काशीमीरा के मीरा गावठण इलाके में स्थित विघ्नहर्ता नामक निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत की है। जहां सोमवार सुबह तेज बरसात के दौरान २४वीं मंजिल पर रखा हुआ भारी भरकम सीमेंट ब्लॉक अचानक गिर गया। यह ब्लॉक इमारत की बगल में स्थित श्री हरिधाम वेलफेयर सोसायटी चॉल के छप्पर को चीरता हुआ एक घर पर गिरा। इस घटना में घर के अंदर मौजूद चार लोगों को गंभीर चोटें लगने की खबर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जख्मी लोगों की पहचान प्रियंका सतीश चौबे, सतीश चौबे, धर्मेंद्र सोनी और संतोष जाधव के रूप में हुई है। प्रियंका चौबे का इलाज ऑर्बिट अस्पताल में चल रहा है, जबकि अन्य तीन घायलों को भायंदर-पश्चिम स्थित पंडित भीमसेन जोशी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, पुलिस घटना के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है। ज्ञात हो कि वायु प्रदूषण पर काबू पाने और लोगों की सुरक्षा हेतु पिछले साल मनपा ने कई दिशा-निर्देशों को पारित किया था, जिसमें निर्माण सामग्री की ढके हुए वाहनों (वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले) में आवाजाही, निर्माणाधीन परियोजनाओ के चारों तरफ ऊंची मेटल शीट की बाउंड्री स्थापित करना और सुरक्षा नेट जाली का अनिवार्य उपयोग जैसे जरूरी मुद्दों का समावेश था। हालांकि, शहर के ज्यादातर

बिल्डर अपने रसूख और राजनीतिक संबंधों के बल पर इन सुरक्षा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं, परिणाम स्वरूप राह चलते / आस-पास रहनेवाले नागरिक, वाहन चालक और निर्माण स्थलों पर काम करनेवाले मजदूरों पर जानलेवा खतरा बना रहता है।

मनपा आयुक्त के आवास पर भी बरसी थी निर्णाण सामग्री

गौरतलब है कि शहर के निर्माण स्थलों पर विकासकों द्वारा खुलेआम हो रही नियमों की अनदेखी ने कुछ महीने पहले मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा के सरकारी आवास पर भी दस्तक दी थी। मनपा आयुक्त के मीरा रोड के कनकिया इलाके में स्थित बंगले (आधिकारिक आवास) में अचानक ही प्लास्टर की बरसात होने लगी। ज्ञात हो की बंगले के ठीक बगल में चल रहे स्काई हाइट्स नामक ३६ मंजिला टावर के निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डर ने प्लास्टर का काम शुरू किया था। प्रक्रिया में सुरक्षा मानकों की कथित अनदेखी के कारण प्लास्टर में इस्तेमाल होनेवाली सामग्री आयुक्त आवास के छत और लॉन पर बरसने लगे थे। जब आयुक्त का बांग्ला ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की हालत का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

डालमिया इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में भीषण आग

मीरा रोड स्थित डालमिया इंटरनेशनल स्कूल की छठी मंजिल पर बने ऑडिटोरियम में बुधवार सुबह करीब छह बजे भीषण आग लग गई। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऑडिटोरियम, कंप्यूटर तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही महानगरपालिका के अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर के समीप स्थित स्कूल में दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। चारों ओर धुएं और आग की ऊंची लपटों से कुछ समय के लिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया। अग्निशमन विभाग ने इमारत को चारों ओर से घेरकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोराडे के नेतृत्व में 43 दमकल कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। आग बुझाने के लिए आठ दमकल वाहन, चार अतिरिक्त पानी के टैंकर तथा टीटीएल वाहन की सहायता ली गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि आग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

110 वर्ष की आयु में धर्मराजी रामकरतार पांडे का निधन, शोक की लहर

परिवार और समाज ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

दीर्घायु जीवन का सफर तय करने वाली धर्मराजी रामकरतार पांडे का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार और शुभचिंतकों में शोक की लहर फैल गई। बताया गया कि उनका निधन 3 जुलाई 2026 को प्राकृतिक कारणों से हुआ। परिवार के अनुसार धर्मराजी पांडे ने अपने जीवनकाल में परिवार के संस्कारों, सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक एकता को हमेशा प्राथमिकता दी।

उनके लंबे जीवन अनुभव और स्नेहपूर्ण स्वभाव ने परिवार की कई पीढ़ियों को मार्गदर्शन देने का कार्य किया। शोकाकुल परिजनों ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ा है। परिवार के सदस्यों और परिचितों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। परिजनों का कहना है कि धर्मराजी पांडे का स्नेह, आशीर्वाद और जीवन मूल्यों की सीख हमेशा परिवार की स्मृतियों में जीवित रहेगी।

21 हादसों के बाद जागा प्रशासन, ठाणे मेट्रो मार्ग की जर्जर सड़कों पर शुरू हुई मरम्मत

ठाणे जिले के मीरा- भाईंदर में मेट्रो लाइन के नीचे की मुख्य सड़कों पर लंबे समय से बने गड्ढों और असमान सतह से परेशान वाहन चालकों को अब राहत मिलने की उम्मीद है।

MMRDA ने संबंधित ठेकेदार के माध्यम से गड्ढों की मरम्मत और सड़क को समतल करने का कार्य शुरू करा दिया है। विभिन्न स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से गड्ढे भरने और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत की जा रही है।

शुरू हुई दहिसर से काशीगांव तक मेट्रो सेवा

दहिसर से काशीगांव तक मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, जबकि काशीगांव से सुभाष चंद्र बोस मैदान तक स्टेशन और ट्रैक निर्माण कार्य जारी है। निर्माण के दौरान मुख्य सड़कें कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे यातायात

प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया।

मेट्रो परियोजना के समझौते के अनुसार इन सड़कों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की है, लेकिन लापरवाही के कारण सड़कें बदहाल हो गई थीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मनपा प्रशासन, MMRDA और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक के बाद मरम्मत कार्य शुरू किया गया।

फिलहाल खतरनाक स्थानों के सड़क को पहले समतल की जा रही है तथा पूरे मार्ग पर चरणबद्ध तरीके से गड्ढे भरे जाएंगे। पिछले तीन महीनों में इन सड़कों पर 21 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 7 लोगों की मौत हुई। लगातार हादसों और प्रशासन से जवाब-तलब के बाद अब मरम्मत कार्य तेज किया गया है।

अभियंता को पत्र लिख समस्या बताई

इस बीच MMRDA ने मीरा- भाईंदर मनपा के शहर अभियंता को पत्र लिख कर मीरा रोड स्थित शहीद भगत सिंह गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास सड़क की खतरनाक असमानता पर चिंता जताई।

पत्र में कहा गया है कि मनपा द्वारा जलापूर्ति की पाइपलाइन बिछाने के बाद मैस्टिक डामर से मरम्मत की गई, लेकिन कंक्रीट और डामर सड़क की ऊंचाई में अंतर रहने से सड़क विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए जोखिमपूर्ण बन गई है। MMRDA ने इस असमानता को तत्काल दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com